[2013]9 एस. सी. आर 295

सुनील दामोदर गायकवाड़

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(आपराधिक अपील सं। 165-166 /2011)

10 सितंबर, 2013

[सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और कुरियन जोसेफ, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1860: की धारा 302 और 307-अभियुक्त ने अपनी पत्नी और 2 बेटों की हत्या की और अपनी बेटी की हत्या का प्रयास किया। अंतर्गत धारा 302 के तहत मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गई और धारा 307 में आजीवन कारावास की सजा– अभिनिर्धारित किया गयाः कम करने वाले और बढाने वाले कारकों की एक 'बेलेंस शीट' तैयार करने के अलावा, सामाजिक-आर्थिक मजबूरियां जैसे गरीबी भी ऐसे कारक हैं जिन पर अदालतों द्वारा सजा सुनाते समय विचार किया जाना चाहिए। हस्तगत मामले में, यह साक्ष्य में आया है कि अभियुक्त आर्थिक और मानसिक मजबूरियों से पीड़ित था-उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था-वास्तव में, उसका इरादा घोर गरीबी के कारण खुद सहित पूरा परिवार को खत्म करने का था- उसे सुधारने और पुनर्वास की संभावना से इन्कार नहीं किया

जा सकता- समाज के लिए खतरा या खतरा होने की संभावना नहीं है- तथ्यों और परिस्थितियों में यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है ताकि मृत्युदंड की सजा दी जा सके -- 'व्यक्तिगत रूप से अनिर्णायक और संचयी रूप से मामूली तथ्य और परिस्थितियाँ' आजीवन कारावास की कम सजा देने की और प्रवृत होती है - धारा 302 की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया जो उसके जैविक जीवन के अंत तक होगा-धारा 307 के तहत सजा घटाकर 7 साल का कठोर कारावास कर दिया गया - यदि आजीवन कारावास की सजा माफ कर दी जाती है या किसी निर्दिष्ट अवधि में परिवर्तित कर दी जाती है, तो धारा 307 के तहत कारावास की सजा इसके बाद शुरू होगी।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: की धारा 354(3) - हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा देना- विशेष कारण दर्ज किए जाने चाहिए-अभिनिर्धारित किया गया, यह नियम के रूप में आजीवन कारावास व अपवाद के रूप में मृत्यु दण्ड को दर्शाता है- धारा 354 (3) के मध्यनजर मृत्युदण्ड की सजा देने से पहले अदालत को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या यह आजीवन कारावास की सजा देने के लिए उपयुक्त मामला है और यदि नहीं तो केवल तभी मृत्युदण्ड की सजा दी जा सकती है-दंड प्रक्रिया संहिता, 1898- धारा 367 (5).

न्यायिक समिति-अभिनिर्धारितः न्यायिक समिति न्यायिक अनुशासन का एक अभिन्न अंग है और न्यायिक अनुशासन की आधारशिला न्यायिक अखंडता है - जब बाध्यकारी निर्णय होते हैं, तो न्यायिक समिति अपेक्षा करती है और उसका पालन करने की आवश्यकता होती है।

अपीलार्थी पर उसकी पत्नी और दो बेटों की मौत का कारण बनने और अपनी बेटी, जिसे उसने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, की हत्या करने का प्रयास करने के लिए मुकदमा चलाया गया था, घटना के बाद अपीलार्थी पुलिस स्टेशन गया और रिपोर्ट दी कि उसका एक बेटा अस्थमा से पीडित है, जिसके लिए लगातार दवा की आवश्यकता होती है। उसकी आय मुश्किल से ही अपने परिवार को बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी। जिसके कारण वह तनाव में था और इसलिए उसने स्वयं सहित पूरे परिवार को खत्म करने का फैसला किया। इस प्रक्रिया में उसने अपनी पत्नी और दो बेटों की एक कैची से मार डाला और अपनी बेटी (पीडब्लू 1) को चाकू मारकर घायल कर दिया और उसके मुँह को तकिये से दबा दिया लेकिन वह मौत के आगे नहीं झुकी; और बच्चे को उसी हालत में छोड़ कर दरवाजे की बाहर से कुंडी लगाकर वह पुलिस स्टेशन पहुँचा। इसकी पुष्टि पी.डब्ल्यू. 4 ने अपने बयान में की। यद्यपि, अपीलार्थी ने अपने कथन धारा313 Cr.P.C में, सब कुछ सामान्य रूप से अस्वीकार कर दिया और कोई साक्ष्य नहीं दी। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 302, 307

भारतीय दण्ड संहिता में दोषी करार दिया, प्रथम मामले में मृत्युदण्ड एवं दूसरे मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

सुनील दामोदर गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य 297

तत्काल अपील में, विचार के लिए एकमात्र मुद्दा मौत की सजा को कम करने का था। न्यायालय ने अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित

1.1. मृत्युदंड देने से पहले, धारा 354(3)Cr.PC के परिप्रेक्ष्य में अदालत को पहले जाँच करनी होगी कि क्या यह आजीवन कारावास की सजा देने के लिए उपयुक्त मामला है और यदि नहीं और केवल तभी मृत्युदण्ड की सजा दी जा सकती है। हत्या के लिए नियम आजीवन कारावास है और मृत्यु एक अपवाद है, जिसके लिए विशेष कारण बताये जाने हैं। बच्चन सिंह मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद मौत की सजा को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी में डाल दिया गया है। उस मामले में निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहले संविधान पीठ द्वारा दिया गया आदेश है कि अदालतों को न केवल अपराध बल्कि अपराधी को भी देखना चाहिए और अपराध के समय अपराधी की परिस्थितयों पर भी उचित विचार करना चाहिए। मच्छी सिंह और शंकर किसनराव खाड़े में कम करने वाले और बढाने वाले कारकों की 'बैलेंस शीट' बनाने पर जोर दिया गया था। [पैरा

15,16,17 और 19] [307-एफ-एच; 308-ए-बी; 309-जी-एच; 310-ए; 311-जी]

बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684 -में अनुसरण किया गया।

मच्छी सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 1983 (3) एस. सी. आर. 413 =(1983) 3 एससीसी 470, शंकर किशनराव खाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 5 एस.सी.सी. 546; दलबीर सिंह बनाम. पंजाब राज्य 1979 (3)एस सी आर 1059 = ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 1384-पर निर्भर था।

1.2. गरीबी जैसी सामाजिक-आर्थिक मजबूरियां भी ऐसे कारक हैं जिनपर अदालतों द्वारा सजा सुनाते समय विचार किया जाना चाहिए, और उपयुक्त मामलों में, न्यायिक परिवर्तन की अनुमति है। [पैरा 21 और 24] [315-डी; 316-एच; 317-ए]

298 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2013] 9 एस. सी. आर

एडिगा अनाम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1974 (3) एससीआर 329 = (1974) 4 एससीसी 443; सुशील कुमार बनाम पंजाब राज्य (2009) 10 एस. सी. सी. 434-पर निर्भर था।

1.3. जब बाध्यकारी निर्णय होते हैं, तो न्यायिक समिति अपेक्षा करती है और उसका पालन करने की आवश्यकता होती है। न्यायिक समिति न्यायिक अनुशासन का एक अभिन्न अंग है और न्यायिक

अनुशासन न्यायिक अखंडता की आधारशिला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि ऐसे नए आयाम हैं जो बडी पीठ के निर्णय के अनुपात के साथ टकराव में नहीं है अथवा जहां कुछ भी जोड़ा और समझाया जाना है, तो उसे पेश करने की हमेशा अनुमति है। इस प्रकार गरीबी, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक मजबूरियाँ, जीवन में अवांछनीय प्रतिकूलताएं कुछ कम करने वाले कारक हैं। बच्चन सिंह और मच्छीसिंह में बताए गए कारकों के अलावा विचार किया गया। इस प्रकार यह न्यायालय सजा पर विचार करते समय बाध्यकारी निर्णयों में संकेतित बढाने और कम करने वाले कारकों के प्रकाश में अपराधी और उसकी परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए बाध्य है। [पैरा 18] [311-सी-एफ]

1.4. वर्तमान मामले में, यह साक्ष्य में आया है कि अपीलार्थी आर्थिक और मानसिक रूप से पीड़ित था, अभियुक्त के सुधार व पुनर्वास की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। न्यायालय के पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अभियुक्त से समाज के लिए खतरा या खतरा होने की संभावना नहीं है। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसकी कोई पूर्व अपराधिक पृष्ठभूमि रही हो. वास्तव में उसका इरादा घोर गरीबी के कारण खुद सहित पूरा परिवार को खत्म करने का था। मामले के इस पहलू की सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने उचित रूप से सराहना नहीं की है। [पैरा 25] [317-जी-एच; 318-ए-सी]

1.5. मामले के तथ्यों और अपराध कारित करते समय अपीलार्थी की परिस्थितियों से यह स्पष्ट

सुनील दामोदर गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य 299 है कि मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है जिनमे मौत की सजा दी जा सके। व्यक्तिगत रूप से अनिर्णायक और संचयी रूप से मामूली तथ्य और परिस्थितियाँ आजीवन कारावास की कम सजा देने की ओर प्रवृत्त होती हैं। इसलिए धारा 302 और धारा 307 आई. पी. सी. के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धी को बरकरार रखते हुए सजा को निम्न निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः

(अ) धारा 302 आईपीसी के तहत अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।

(ब) धारा 307 आईपीसी के दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को सात साल की कारावास की सजा सुनाई जाती है

गोपाल विनायक गोडसे मामले में संविधान पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि किसी दोषी को आजीवन कारावास की सजा उसके जैविक जीवन के अंत तक दी जाती है। हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि मामले में आजीवन कारावास की सजा को कम कर दिया जाता है या किसी निर्दिष्ट अवधि (धारा 433 ए, Cr.P.C के मध्यनजर चौदह वर्ष से कम

नहीं होगी) में बदल दिया जाता है तो धारा 307 के तहत कारावास की सजा उसके बाद शुरू होगी। [पैरा 26-28] [318-G-H; 319-A-E]

गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 1961 एस. सी. आर. 440 = ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 600-पर निर्भर किया।

केस लॉ रेफरेंस

1974 (3) एससीआर 329 रिलाइड ऑन पैरा 4

1979 (3) एससीआर 1059 रिलाइड ऑन पैरा 16

1983 (3) एससीआर 413 रिलाइड ऑन पैरा 17

(2013) 5 एस. सी. सी. 546 रिलाइड ऑन पैरा 19

(2009) 10 एस. सी. सी. 434 रिलाइड ऑन पैरा 24

1961 एससीआर 440 रिलाइड ऑन पैरा 28

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील नं. 165-166/2011

300 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2013]9 एस. सी. आर.

बॉम्बे में उच्च न्यायालय के अपील संख्या 280/2009 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 23.09.2010 से उत्पन्न।

रमेश चंद्र मिश्रा, डॉ. मीरा अग्रवाल अपीलार्थी की और से।

सुशील करंजकर, आशा गोपालन नायर प्रत्यर्थी की ओर से न्यायालय का निर्णय कुरियन, जे. द्वारा सुनाया गया

1. जहां तक मृत्युदण्ड का प्रश्न है, मृत्यु और यदि जीवन नहीं, तो मृत्यु या जीवन, जीवन और यदि मृत्यु नहीं, तो यह भारत में आपराधिक न्यायशास्त्र की बदलती प्रगति है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1898, की धारा 367 (5) में कहा गया हैः

> " यदि अभियुक्त को मृत्युदण्ड से दण्डनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और अदालत उसे मृत्युदण्ड के अलावा कोई अन्य सजा देती है तो न्यायालय अपने निर्णय में बताएगा कि मौत की सजा क्यों नहीं दी गई "।
>
> (जोर दिया गया)

मृत्यु को नियम बनाने वाले इस प्रावधान को 1955 के अधिनियम 26 द्वारा हटा दिया गया था।

2. हमारे संविधान के पहले दशक के दौरान मृत्युदंड के उन्मूलन पर व्यापक चर्चा और अध्ययन हुए है। और स्वयं संसद ने एक स्तर पर भारत के विधि आयोग के विचार जानने की इच्छा व्यक्त की थी और तदनुसार, आयोग ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, रिपोर्ट, रिपोर्ट संख्या 35 दिनांक 19.12.1967 विधि आयोग की 35 वीं रिपोर्ट का संदर्भ हमारी चर्चा के लिए प्रासंगिक होगी। उद्धृत करने के लिएः

> " 21 अप्रैल 1962 को लोकसभा में एक प्रस्ताव मृत्युदंड के उन्मूलन के लिए पेश किया गया था। प्रस्ताव पर बहस के

दौरान सुझाव दिए गए कि प्रश्न पर विचार करने के लिए एक आयोग या समिति नियुक्त की जानी

सुनील दामोदर गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य [कुरियन, जे.] 301 चाहिए। हालांकि, अंततः,सदन में हुई थी चर्चा की एक प्रति विधि आयोग को भेजी गयी जिसने उस समय दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता की जांच के प्रश्न को जब्त कर लिया था।

विधि आयोग ने इस विषय को देश के सामान्य आपराधिक कानून के संशोधन से अलग रखना वांछनीय समझा। ऐसा विषय के महत्व, की विशाल प्रकृति और बडी संख्या में विस्तृत प्रश्नों के कारण था। जिनकी जाँच की जानी थी। इस मामले पर संसद में किसी न किसी रूप में बार-बार चर्चा हुई थी और इसलिए आयोग ने इस पर विचार करना कुछ जरूरी समझा। अन्य देशों में भी, इस विषय को स्पष्ट रूप से अलग व पूर्ण अध्ययन के लिए एक माना गया था"

3. ऐसा प्रतीत होता है कि संसद ने अंततः भारतीय दंड संहिता में मृत्युदण्ड को बरकरार रखने का फैसला किया। हालाँकि, जब वर्ष 1973 में नई दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई (इसके बाद इसे 'Cr.PC') के रूप में

संदर्भित किया गया, एक आदर्श बदलाव पेश किया गया, जिससे न्यायालयों के लिए मौत की सजा देने के लिए विशेष कारण बताना अनिवार्य हो गया। धारा 354 (3) जो इस प्रकार हैः

> "जब दोषसिद्धि मृत्युदण्ड से दंडनीय अपराध के लिए होती है-या, वैकल्पिक रूप से, आजीवन कारावास या कई वर्षों की अवधि के लिए कारावास के लिए हो, निर्णय में दी गयी सजा के कारण बताये जाएंगे, और मृत्युदण्ड के मामले में, इस तरह की सजा के विशेष कारण।''

(जोर दिया गया)

4. एडिगा अनम्मा बनाम. आंध्र प्रदेश राज्य (1974) 4 एससीसी 443 में कृष्ण अरययर जे. के शब्दों में 302 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2013]9 एस सी आर।

> " 20. विधायी महत्व में स्पष्ट बदलाव यह है कि हत्या के लिए आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदण्ड एक अपवाद है। जिसका सहारा लिया जाना चाहिए।
>
> 21. यह स्पष्ट है कि मृत्यु की सजा के माध्यम से जीवन के लिए कानूनी खतरे के जटिल प्रश्न पर राज्य की विचलित अंतरात्मा ने खुद को विधायी रूप से व्यक्त करने की मांग

की है, प्रवृति की धारा सतर्क, आंशिक उन्मूलन और पूर्ण प्रतिधारण से पीछे हटने की और है।''

(जोर दिया गया)

5. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि किसी भी सजा को कई वर्षों की अवधि के लिए देने के लिए बताए जाने वाले कारणों की आवश्यकता को 1973 में पहली बार Cr.PC में विधायी अभिव्यक्ति पाई गई, मृत्युदंड के मामले में, विशेष कारण होने चाहिए। यह नियम के रूप में आजीवन कारावास और अपवाद के रूप में मृत्यु के प्रतिमान परिवर्तन को दर्शाता है।

6. जहाँ तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, मृत्युदंड पर उपरोक्त प्रारंभिक चर्चा का विशेष महत्व है। हमारे समक्ष अपीलार्थी ने धारा 302 सपिठत धारा 307 आईपीसी. के तहत मुकदमे का सामना करना पडा। सत्र न्यायालय ने उन्हें दोनों धाराओ के तहत दोषी ठहराया। धारा 302 के तहत मृत्युदण्ड और धारा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। संदर्भ पर उच्च न्यायालय ने मृत्युदण्ड की सजा की पुष्टि की। उच्चन्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को धारा 307 के तहत दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया गया। इस प्रकार, व्यथित होकर वर्तमान अपीलें करता हैं।

7. भारी सबूतों को देखते हुए, हालांकि अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील मुख्य रूप से मृत्युदंड को कम करने के लिए प्रचार

कर रहे थे, हम अपने विवेक को संतुष्ट कर सकें, हम तथ्यों, साक्ष्य और तर्कों का संक्षेप में, गुणदोष के आधार पर भी उल्लेख कर सकते हैं।

303 सुनील दामोदर गायकवाड़ बनाम। का महाराष्ट्र राज्य (कुरियन, जे.)

8. अपीलार्थी की शादी संगीता नाम की महिला से हुई थी। उनके तीन बच्चे थे, एक बेटी और दो बेटे। वे उसकी मौसी के घर में दो कमरों में रह रहे थे। वे पेशे से एक दर्जी थे और कपड़े की दुकान में काम करते थे। उनका एक बेटा आकाश अस्थमा से पीड़ित था जिसके लिए उसे लगातार दवा की आवश्यकता होती थी। अपीलार्थी की आय अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त थी और वह इस संबंध में तनाव में था। 08.07.2008 को, यह कहा गया है कि इस दौरान सुबह के शुरुआती घंटे जब परिवार के सदस्य सो रहे थे, उसने अपनी पत्नी संगीता और अपने दो बेटों पर एक एक तेज कैंची से अलग-अलग हिस्सों से हमला किया और कई चोटें पहुंचाईं जिससे उनकी तत्काल मौत हो गई। उसकी बेटी गायत्री उर्फ पूजा को भी उसने चाकू से वार कर घायल कर दिया। हालाँकि, वह किसी तरह बोल पायी और उसने अपने पिता अपीलार्थी से पूछा की वह उसे क्यों घायल कर रहे हैं। अपीलार्थी पिता ने उसे बताया कि पूरे परिवार को जाना होगा और वह भी उनके पीछे चलेगा। हालांकि उसने उसे पीने के लिए पानी दिया। इसके बाद वह उसे अपनी गोद में ले लिया

और उसका दम घोटने के इरादे से उसके मुंह को एक तकिये से दबाया और फिर भी बच्ची की मौत नहीं हुई। उसने बच्चे को उस हालत में छोड़ दिया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और सीधे पुलिस स्टेशन गया और घटना की सूचना दी। एक एफ़. आई. आर. दर्ज की गई। उनका बयान दर्ज किया गया। इस बीच बेटी गायत्री को एक पड़ोसी से मदद मिली और तुरंत एक अस्पताल में इलाज किया गया और इस प्रकार वह बच गयी। वह प्रमुख गवाह है-पीडब्लू1। पड़ोसी अभियुक्त की नानी पीडब्लू 4 है।

9. अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह परीक्षित करवाए और मुख्य रूप से पीडब्लू.1 गायत्री की साक्ष्य के कथनों के आधार पर अपीलार्थी को धारा302 और 307 के तहत दोषी ठहराया गया। गायत्री उर्फ पूजा जाँच के दौरान और साथ ही सत्र न्यायालय के समक्ष स्पष्ट और सुसंगत थी।

' ..... घर में मेरे पिता, माँ और हम सभी बच्चे थे। मेरे पिता ने मेरी मां, मेरे दो भाइयों और मुझ पर कैची से हमला किया। मेरे दो भाइयों और माँ की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मेरी छाती, पेट व दोनों हाथों पर हमला

304 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2013] 9 एस. सी. आर. किया गया। मैंने अपने पिता से पूछा कि वह हम पर हमला क्यो कर रहे हैं, हालांकि हमने कुछ नहीं किया। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि हम सभी को जाने की जरूरत है और वह हमारा पीछा कर रहा होगा। फिर मेरे पिता ने

मुझे पीने के लिए पानी दिया। फिर उन्होंने मुझे अपनी गोद में ले लिया और फिर तकिए की मदद से मेरा मुंह दबाया। इसके बाद वह थाने पहुंचा। बाहर जाते समय उन्होंने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। एक सखारबाई सदाशिव सोनवाने उनके पड़ोस में उसी मकान में रहता थी। मैं मदद के लिए चिल्लाई। मैंने उसे हमें बचाने के लिए कहा और हमारा खून बह रहा है। फिर उसने दरवाज़ा खोला। फिर मेरे चाचा अनिल गायकवाड़ वहाँ आए और हमें गेवराइ स्थित सरकारी अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। वहाँ से मुझे मेरे चाचा बीड सिविल अस्पताल लाए। पुलिस अस्पताल में पूछताछ करने के लिए मेरे पास आई थी। मैंने पूरी घटना सुनाई। कटघरे में अभियुक्त मेरे पिता हैं। अभियुक्त एक दर्जी था और वह किसी अनिल की दुकान में काम कर रहा था। आज मुझे दिखाई गई कैंची को मैं पहचान सकती हूँ। (गवाह ने न्यायालय में आर्टिकल संख्या 15 कैंची की पहचान की)। मैं लगभग 21 दिनों तक अस्पताल में रही।

(जोर दिया गया)

प्रतिपरीक्षण में, उसने इस प्रकार कहाः

> "..... हम आर्थिक रूप से गरीब हैं। मेरे पिता त्यौहार के मौसम में पूरे दिन और कभी-कभी पूरी रात दुकान में काम करते थे। यह सच है कि कभी कभी वह पूरी रात दुकान पर रहता था और अगले दिन वापस आ जाता था। वह हमारे

लिए दुकान में काम करके पैसे कमाता था।..... यह कहना सही नहीं है कि मैं यह नहीं बता पा रही हूं कि मेरी मां और भाइयों को किसने मारा, क्यों कि मैं सो रही थी।..... यह सच नहीं है कि मैं अपने चाचा और पुलिस के कहने पर अभियुक्त के खिलाफ गवाही दे रही हूं। (जोर दिया गया)

सुनील दामोदर गायकवाड़ बनाममहाराष्ट्र राज्य [कुरियन, जे.] 305

10. पीडब्लू 2 पंच गवाह है। पीडब्लू3 डॉक्टर हैं-डॉ क्रांति राउत, जिन्होंने शव परीक्षण किया। सभी तीन मृतकों के मामलों में, डॉक्टर ने राय दी है कि मृत्यु महत्वपूर्ण अंगों पर कई छुरा घोंपने की चोटों के कारण हेमोथोरैक्स के साथ रक्तस्राव सदमे के कारण हुई थी। एफएसएल रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि अपीलार्थी और उसकी मृत पत्नी के कपड़ों पर खून एक ही समूह का था। डॉक्टर साहब ने पी. डब्ल्यू.

1. गायत्री उर्फ पूजा का भी इलाज किया है और उसका उसे लगी कई चोटों का विवरण का उल्लेख किया है। यह भी दर्शाया गया है कि चोट नं. 4, जो चाकू का घाव है, यदि समय पर उपचार ना किया जायें तो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। डॉक्टर ने कहा कि मृतक व्यक्तियों के साथ-साथ घायल पीडब्लू1-गायत्री को सभी चोटें हथियार आर्टकल न.6 कैची से आना सम्भव हैं। पीडब्लू4

सखारबाई अपीलार्थी की चाची हैं। उन्होंने कहा है कि अपीलार्थी का बड़ा बेटा दमे से पीड़ित था। उसने निम्नलिखित रूप में भी कथन कियाः

> "जब मैं अपने घर पर सो रहा था, सुबह करीब 5.30 बजे मैं बरतन धो रहा था, मैने गायत्री की आवाज सुनी जो मुझे दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी और कह रही थी कि उसके पिता ने उन पर हमला किया। मैं कमरे के पास गया और पाया कि दरवाजा बाहर से बंद था जिसे मैंने खोला और कमरे के अंदर चला गया। मैंने देखा कि संगीता, ओमकार, आकाश खून से लथपथ पडे थे और वे मर चुके थे। गायत्री के भी उसकी छाती, पेट और ठोड़ी पर खून बहने की चोटें थी। उसने मुझे बताया कि उसके पिता ने उस रात उन सभी पर कैंची से हमला किया उस रात। मैं चिल्लाते हुए बबन, अनिल के पास गया और उन्हें बुलाया। उक्त अनिल गायत्री को अस्पताल ले गया। गायत्री को पूजा के नाम से भी जाना जाता है।"

(जोर दिया गया)

क्रॉस में, उसने बताया किया कि

> "अभियुक्त एक दर्जी था। यह सच है कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी।"

11. पीडब्लू5 वह है जिसने अपीलार्थी को कैंची बेची थी। पीडब्लू6 अपराध के हथियार और अभियुक्त द्वारा पहनी गई अन्य पोशाक की बरामदगी का पंच गवाह है।

पीडब्लू 7 पुलिस उप निरीक्षक है। उनके अनुसार, अपीलार्थी ने उन्हें बताया था कि सुबह करीब 5.30 बजे उसने अपनी पत्नी और दो बेटों की हत्या कर दी है और उसकी बेटी गायत्री को घायल कर दिया है। बयान-प्रदर्शन सं. 29 उसके द्वारा दर्ज किया गया था और अपीलार्थी ने उसपर हस्ताक्षर किए। पीडब्लू8 पुलिस निरीक्षक है जिसने अनुसंधान किया । पीडब्लू9 पुलिस निरीक्षक है जिसने पूछताछ और घटनास्थल का पंचनामा तैयार किया। उन्होंने घटनास्थल से खून और खून से सना तकिया का कवर को इकटठा किया। उन्होंने अभियुक्त द्वारा बताए गए कैंची की बरामदगी भी की। तस्वीरें भी खींची गईं। हम अपीलार्थी द्वारा स्वयं पुलिस के समक्ष दिया गया बयान का भी उल्लेख कर सकते हैं जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थीः

> "मेरे परिवार में मेरा बेटा ओमकार अस्थमा के कारण लगातार बीमार रहता है। उसके उपचार के लिए पैसों की आवश्यकता थी। जो मैने उधार लिये इसलिए मैं कर्ज में डूब गया था। तनाव के कारण मैं अपने काम पर ध्यान केंद्रित

नहीं कर सका और मुझे अक्सर छुट्टी पर जाना पड़ता था। ..... चूंकि मैं तंग आ गया था, मैने धर छोडने का फैसला किया। मेरी पत्नी और बच्ची भूख और बीमारी से मर जाते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद उन्हें राहत दूंगा। "

(जोर दिया गया)

फिर उसने अपनी पत्नी और दो बेटों की हत्या करने का तरीका बताया है। जहाँ तक बेटी पर हमले की बात है, वह निम्नलिखित रूप में वर्णित हैः

" ..... इसके बाद मैंने अपनी बेटी के सीने पर 2-3 वार किए। जिसके कारण वह जागी और मुझे वार करते देख उसने रोते हुए पूछा, ''पापा आपने ऐसा क्यों किया उस समय मैने उत्तर दिया, ''हम सबको जाना है, मैं भी आ रहा हूं''

उसका सिर अपनी गोद में रखा। उसे माने के लिए मैने उसका मुंह और नाक दबाए रखा लेकिन वह मर नहीं रही थी। मैंने कुछ देर इंतजार किया।

जो घटना हुई थी, उससे मैं डरा हुआ था। फिर मैंने उसके पास पानी रखा और उसे घायल हालत में छोड़ दिया।

इसके बाद मैने अपराध के समय पहने हुए कपडे उतार दिये। मैंने अपराध के लिए इस्तेमाल की गई कैंची को एक कपडे में लपेटा और पुलिस स्टेशन गया और खुद को प्रस्तुत किया और घटना की जानकारी दी। (जोर दिया गया)

12. हालाँकि, धारा 313 के बयान के तहत, उन्होंने हर बात से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया लेकिन बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया।

13. सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के आचरण पर विस्तार से चर्चा की। न्यायालय ने मुख्य तर्क पर भी विचार किया कि वह घटना में शामिल नहीं था। दोनों न्यायालयों ने ने पाया है कि उनके तर्को की सराहना करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में पिता का सामान्य आचरण सबसे पहले बच्चे को स्वयं या पड़ोसी कमरों और आस-पास रहने वालों की सहायता से उपचार प्राप्त करने में मदद करना होगा। यह कहने के लिए कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, जिनमें से कुछ का हमने ऊपर उल्लेख किया है, संदेह से परे यह स्थापित करेगा कि केवल अभियुक्त ही अपराध करने में शामिल था।

14. इसलिए, हम सजा के सवाल पर विचार करेंगे। सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय का विचार है कि मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी के अंतर्गत आता है और अपीलार्थी किसी दया के योग्य नहीं था।

15. मृत्युदंड देने से पहले, धारा 354 (3) Cr.PC को ध्यान में रखते हुए, अदालत को पहले यह जांचना होगा कि क्या यह आजीवन कारावास की सजा देने के लिए उपयुक्त मामला है और यदि नहीं और केवल तब मृत्युदंड दिया जा सकता है। अतिरेक के जोखिम पर, हम ध्यान दे सकते हैं कि हत्या के लिए आजीवन कारावास का नियम है, और मृत्यु एक अपवाद है जिसके लिए विशेष कारण बताए जाने हैं।

16. बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684 के मामले में संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय के बाद मौत की सजा को दुर्लभ से 'दुर्लभतम' मामलों में सीमित कर दिया गया है।

308 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2013]9 एस.सी.आर. के बच्चन सिंह के मामले में (ऊपर) में निर्णय का महत्वपूर्ण पहलू संविधान पीठ द्वारा निर्धारित आदेश है कि अदालतों को न केवल अपराध को देखना चाहिए बल्कि अपराधी को भी देखना चाहिए और अपराध करने का समय अपराधी की परिस्थितियों पर भी उचित विचार करना चाहिए।। यह निर्णय आज भी इस क्षेत्र में लागू है और मृत्यु के विषय पर कोई चर्चा बच्चन सिंह के मामले (ऊपर) संदर्भ के बिना पूरी नहीं होती है। उद्धृत करने के लिएः

" 201 ..... जैसा कि हम धारा 354 (3) और 235(2) और 1973 की संहिता के अन्य संबंधित प्रावधानों को पढ़ते हैं। यह हमारे लिए काफी स्पष्ट है कि सजा का विकल्प चुनने या "विशेष कारणों" के अस्तित्व या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए उस संदर्भ में, न्यायालय को अपराध और अपराधी दोनों पर उचित ध्यान देना चाहिए। बढाने और कम करने वाले कारकों को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अक्सर, ये दोनों पहलू इतने आपस में जुड़े हुए हैं कि उनमें से प्रत्येक को अलग-अलग उपचार देना मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 'स्टाइल इज द मैन' है। कई मामलों में, हत्या करने का बेहद क्रूर या पाशविक तरीका स्वयं अपराधी के भ्रष्ट चरित्र का एक प्रदर्शित सूचकांक है। इसलिए अपराध की परिस्थितियों और अपराधी की परिस्थितियों पर दो अलग-अलग निर्विवाद डिब्बों में विचार करना वांछनीय नहीं है। एक अर्थ में हत्या करना क्रूर है और इसलिए सभी हत्याएं क्रूरता है लेकिन ऐसी क्रूरता की दोषिता की डिग्री अलग अलग हो सकती है और यह केवल तभी होता है जब दोषी

अत्यधिक भ्रष्टता का अनुपात मानता है कि "विशेष कारणों को वैध रूप से अस्तित्व में कहा जा सकता है।

XXX XXX XXX

209. कई अन्य परिस्थितियाँ हैं जो हल्की सजा के पारित होने को उचित ठहराती हैं।

सुनील दामोदर गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य [कुरियन, जे.] 309

क्योंकि उत्तेजना की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं।

"हम स्पष्ट रूप से ऐसी सभी स्थितियों को न्यायिक कंप्यूटर में दर्ज नहीं कर सकते क्यों के वह एक अपूर्ण और उतार चढाव वाले समाज में ज्योतिषीय रूप से असम्भव है।"

फिर भी, इस बात पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है कि मृत्युदंड के क्षेत्र में कम करने वाले कारकों का दायरा और अवधारणा को धारा 354 (3) में दी गयी सजा नीति के अनुरूप अदालतों द्वारा एक उदार और व्यापक निर्माण प्राप्त होना चाहिए। न्यायाधीशों को कभी रक्तपिपासु नहीं होना चाहिए। हत्यारों को फांसी देना उनके लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा। भारत संघ द्वारा प्रस्तुत तथ्य और आंकड़े, भले ही अधूरे हों, यह दर्शाता है कि अतीत में, अदालतों ने बहुत कम बार अत्यधिक दंड दिया है।

एक ऐसा तथ्य जो उस सावधानी और करूणा को प्रमाणित करता है जिसे वे हमेशा अपने आचरण में लाते रहे हैं। इतने गंभीर मामले में सजा देना उनका विवेक है इसलिए यह चिंता व्यक्त करना अनिवार्य है कि अदालतें, हमारे द्वारा दर्शाई गई व्यापक सचित्र दिशा निर्देशों की सहायता से धारा 354 (3) में उल्लिखित विधायी नीति का उच्च मार्ग के लिए निर्देशित अधिक ईमानदारी से देखभाल और मानवीय चिंता के, साथ इस महत्वपूर्ण कार्य का निर्वहन करेगा अर्थात्, हत्या के दोषी व्यक्तियों के लिए, आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है। मानव जीवन की गरिमा के लिए एक वास्तविक और स्थायी चिंता कानून के माध्यम से किसी की जान लेने के विरोध को दर्शाती है। दुर्लभतम मामलों को छोड़कर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए जब वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से बंद कर दिया गया है। (जोर दिया गया)

17. मच्छी सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य (1983) 3 एससीसी 470 में तीन-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय ने बच्चन सिंह के मामले में (ऊपर) में बताए गए दिशा-निर्देशों को हटा दिया, जिन्हें मृत्युदण्ड की सजा देते समय प्रत्येक मामले पर लागू करना आवश्यक होगा। मच्छी सिंह के मामले में (ऊपर) के निर्णय में कम करने वाले व बढाने वाले कारकों की 'तुलनपत्र' बनाने पर जोर दिया गया था।

" 38. XXX XXX XXX

(I) अत्यधिक दोषपूर्णता के गंभीरतम मामलों को छोड़कर मौत की कठोर सजा देने की आवश्यकता नहीं है।

(II) मृत्युदंड का विकल्प चुनने से पहले 'अपराध' की परिस्थितियों के साथ साथ 'अपराधी' की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है

(iii) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है। दूसरे शब्दों में, मृत्युदण्ड तभी दिया जाना चाहिए जब अपराध की प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास पूरी तरह से अपर्याप्त सजा प्रतीत हो और बशर्ते, और केवल यह प्रदान किया गया हो कि आजीवन कारावास की सजा देने का विकल्प विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों तथा सभी प्रासंगिक परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए।

(iv) गम्भीर और कम करने वाली परिस्थितियों की एक बैलेंस शीट तैयार करनी होगी। और ऐसा करने में कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व देना होगा और

विकल्प के प्रयोग से पहले गम्भीर और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक न्यायपूर्ण संतुलन बनाना होगा।

39. इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उत्तर दिए जा सकते हैंः

(अ) क्या अपराध में कुछ असामान्य है? जो आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त बनाता है और मृत्युदंड की मांग करता है?

(ब) क्या अपराध की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अपराधी की पक्ष में बोलने वाली परिस्थितियों को अधिकतम महत्व देने के बाद भी मृत्युदंड देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है,

सुनील दामोदर गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य [कुरियन, जे. जे.। 311

40. यदि उपरोक्त प्रस्ताव के आलोक में सभी परिस्थितियों का समग्र वैश्विक दृष्टिकोण लेते हुए और ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए, मामले की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मौत की सजा जरूरी है, अदालत ऐसा करेगी"।

(जोर दिया गया)

18. जब बाध्यकारी निर्णय होते हैं, तो न्यायिक समिति अपेक्षा करती है और उसका पालन करने की अपेक्षा करती है। न्यायिक समिति न्यायिक अनुशासन का एक अभिन्न अंग है और न्यायिक अनुशासन न्यायिक अखंडता की आधारशिला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि नए आयाम वृहद पीठ के निर्णयों के अनुपात के साथ टकराव में नहीं हैं या जहाँ कुछ भी जोड़ा और समझाया जाना है, वहाँ हमेशा उसी को पेश करने की अनुमति है। गरीबी, सामाजिक-आर्थिक, मानसिक मजबूरियां, जीवन में प्रतिकूलताएँ बच्चन सिंह और मच्छी सिंह वाले मामले में बताये गए कारकों के अलावा विचार किये जाने वाले कुछ कम करने वाले कारक हैं। इस प्रकार, हम सजा पर विचार करते समय बाध्यकारी निर्णयों में संकेतित बढाने और कम करने वाले कारकों के आलोक में तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए बाध्य हैं जिन्होंने अपराध के कमीशन, अपराधी और उसकी परिस्थितयों को प्रभावित किया है।

19. शंकर किसनराव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 5 एससीसी 546 के हाल ही के एक निर्णय में इस न्यायालय ने बच्चन सिंह (ऊपर) के बाद मृत्युदंड और उसमें निर्धारित सिद्धांतों पर इस न्यायालय द्वारा दिए गए लगभग सभी निर्णयों को स्केन किया है और उसमें निर्धारित सिद्धांतों को बहाल किया गया है। हाल के निर्णयों (पंद्रह वर्षों) का उल्लेख करते

हुए, मृत्युदण्ड देने के लिए गम्भीर कारकों के रूप में माने जाने वाले प्रमुख कारणों को संदर्भ के साथ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

312 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2013] 9 एस सी आर

शंकर किसनराव के मामले में (ऊपर): के पैरेग्राफ 122 को उद्धरत करने के लिएः

122. उपरोक्त मामलों में मृत्यु की पुष्टि करने के प्रमुख कारणों में शामिल हैंः

> "(1) अपराध की क्रूर, पैशाचिक नृशंस, दुष्ट और वीभत्स प्रकृति (जुम्मन खान 5, धनंजय चटर्जी 6, लक्ष्मण नाइक 7, कामता तिवारी8, निर्मल सिंह 9, जय कुमार 10,सतीश 11,बंटू 12, अंकुश मारुति 13, बी. ए. उमेश 14, मोहम्मद मन्नान 15 और राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक 16);
>
> (2) अपराध के परिणामस्वरूप सार्वजनिक घृणा होती है, न्यायिक विवेक या समाज या समुदाय की अंतरात्मा को झटका लगता है (धनंजय चटर्जी (ऊपर), जय कुमार (ऊपर), अंकुश मारुति शिंदे (ऊपर) और मोहम्मद मन्नान (ऊपर));
>
> ----------
>
> ----------

5. जुम्मन खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1191) 1 एस. सी. सी. 752: (1991) एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 283.

6. धनंजय चटर्जी बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य, (1994) 2 एस. सी. सी. 220: (1994) एससीसी (सी. आर. आई) 358

7. लक्ष्मण नाइक बनाम उड़ीसा राज्य, (1994) 3 एससीसी 381: (1994) एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 656

8. कामता तिवारी बनाम एम. पी. राज्य, (1996) 6 एस. सी. सी. 250: (1996) एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1298

9. निर्मल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (1999) 3 एससीसी 670: (1999) एससीसी (सीआरआई) 472.

10. जय कुमार बनाम एम. पी. राज्य, (1999) 5 एस. सी. सी. 1: (1999) एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 638

11. यू. पी. बनाम राज्य सतीश (2005) 3 एस. सी. सी. 114: (2005) एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 642।

12. बंटू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 11 एस. सी. सी. 113: (2009) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 353।

13. अंकुश मारुति शिंदे बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एस. सी. सी. 667: (2009) 3(सी. आर. आई) 308।

14. बी. ए. उमेश बनाम कर्नाटक राज्य (2011) 3 एस. सी. सी. 85: (2011) 1 एससीसी (सीआरआई) 801

15. मोहम्मद. मन्नान बनाम बिहार राज्य, (2011) 5 एससीसी 317: (2011) 2 एससीसी (सीआरआई) 626.

सुनील दामोदर गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र का राज्य[कुरियन, जे.] 313

16. राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2012) 4 एस. सी. सी. 37: (2012) 2 एससीसी (सीआरआई) 30.

(3) दोषी का सुधार या पुनर्वास की संभावना नहीं है या वह समाज के लिए खतरा होगा (जय कुमार(ऊपर), बी. ए. उमेश (ऊपर) और मोहम्मद मन्नान (ऊपर));

(4) पीड़ित असहाय थे (धनंजय चटर्जी (ऊपर), लक्ष्मण नाइक (ऊपर), कामता तिवारी (ऊपर), अंकुश मारुति शिंदे (ऊपर), मोहम्मद मन्नान (ऊपर) और राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक ((ऊपर)));

(5) अपराध या तो बिना उकसावे के किया गया था या यह पूर्व नियोजित था (धनंजय चटर्जी (ऊपर), लक्ष्मण नायक (ऊपर), कामता तिवारी (ऊपर), निर्मल सिंह (ऊपर), जय कुमार (ऊपर), अंकुश मारुति शिंदे (ऊपर), बी. ए. उमेश (ऊपर) और मोहम्मद मन्नान (ऊपर)) और तीन मामलों मे पूर्ववृत्त या दोषी का पूर्व इतिहास ध्यान में रखा गया था (शिवु(17) बी. ए. उमेश (ऊपर) और राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक (ऊपर))।"

(जोर दिया गया)

20. हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा को नियंत्रित करने वाले कम करने वाले कारकों को पैरैग्राफ 106. में संक्षेपित किया गया है। उद्धृत करने के लिएः

" 106. उपरोक्त मामलों के अध्ययन से पता चलता है कि मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में बदलने के लिए कई कारण हैं, हालांकि, कुछ कारक जिनका प्रभाव पड़ा है, उनमें शामिल हैंः

(1) अभियुक्त की कम उम्र [अमित बनाम महाराष्ट्र(18) राज्य उम्र 20 साल, राहुल (19)उम्र 24 साल, संतोष कुमार सिंह(20), उम्र 24 वर्ष, रमेशभाई चंदूभाई राठौड (2) (21)

आयु 28 वर्ष और अमित बनाम उत्तरप्रदेश राज्य (22)28 वर्ष की आयु

---

17 शिवू बनाम कर्नाटक उच्च न्यायालय, (2007) 4 एस. सी. सी. 713: (2007) 2 एससीसी (सीआरआई)686 .

18 (2003) 8 एससीसी 93: (2003) एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1959

19 राहुल बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2005) 10 एससीसी 322: (2005) एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1516

20 संतोष कुमार सिंह बनाम राज्य, (2010) 9 एससीसी 747 (2010) 3 एससीसी (सीआरआई) 1469.

(2) अभियुक्त में सुधार और पुनर्वास की संभावना (संतोष कुमार सिंह (ऊपर) और अमित बनाम यू.पी. राज्य (ऊपर) अभियुक्त, संयोग से, युवा थे जब उन्होंने अपराध किया था);

(3) अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था (निर्मल सिंह (ऊपर), राजू (23), बंटू (ऊपर), अमित बनाम महाराष्ट्र (ऊपर), सुरेंद्र पाल शिवबालकपा(24), राहुल (ऊपर) और अमित बनाम यू.पी. राज्य (ऊपर)

(4) अभियुक्त के समाज या समुदाय के लिए खतरा या खतरा होने की संभावना नहीं थी। (निर्मल सिंह (ऊपर), मोहम्मद. चमन (25), राजू (सुप्रा), बंटू (सुप्रा), सुरेंद्र पाल शिवबालकपाल (सुप्रा), राहुल (सुप्रा) और अमित बनाम यू. पी. राज्य (ऊपर));

(5) कुछ अन्य कारणों का उल्लेख करने की आवश्यकता है जैसे कि अभियुक्त को एक अदालत द्वारा बरी कर दिया गया है (राज्य टी. एन. बनाम. सुरेश (26), महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश (27), भारत फकीरा धीवर (28), मानसिंह(29) और संतोष कुमार सिंह (ऊपर));

---

21. (2011) 2 एससीसी 764: (2011) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 883.

22. (2012) 4 एससीसी 107: (2012) 2 एससीसी (सीआर) 590

23. राजू बनाम हरियाणा राज्य, (2001) 9 एससीसी 50: (2002) एससीसी (सीआरआई) 408।

24. सुरेंद्र पाल शिवबलकपाल बनाम गुजरात राज्य, (2005) 3 एस. सी. सी. 127: (2005) एस. सी. सी. (सी.आर.आई) 653.

25. मोहम्मद. चमन बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (2001) 2 एस. सी. सी. 28: (2001) एससीसी(सी.आर.आई) 278

26. (1998) 2 एससीसी 372: (1998) एससीसी (सीआरआई) 751

27. (2000) 1 एससीसी 471: (2000) एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 263.

28. महाराष्ट्र राज्य बनाम भारत फैकरा धीवार, (2002)1 एस. सी. सी. 622:(2002) एससीसी (सीआरआई) 217

29. महाराष्ट्र राज्य बनाम मान सिंह (2005) 3 एस. सी. सी. 131: (2005) एससीसी (सीआरआई) 657.

(6) अपराध पूर्व नियोजित नहीं था (कुमुदी लाल (30) अख्तर (31), राजू (ऊपर) और अमृत सिंह (32);

(7) मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों में से एक था (मानसिंह (ऊपर) और बिष्णु प्रसाद सिन्हा (33)

एक मामले में, कम करने का आदेश दिया गया था क्योंकि स्पष्ट रूप से मृत्युदण्ड की कोई "अपवादिक" कारक नहीं थे। (कुमुदी लाल (ऊपर)) और दूसरे मामले में क्योंकि निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे बढाकर मृत्युदण्ड कर दिया था (हरेश मोहनदास राजपूत (34)'' (जोर दिया गया)

21. इस समय, एडिगा अनाम्मा के मामले (ऊपर) का उल्लेख करना भी उपयोगी हो सकता है। इस मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां अपराधी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक या दंडात्मक मजबूरियों से पीडित है, जो कानूनी अपवाद को आकर्षित करने या अपराध को कम करने के लिए अपर्याप्त हैं, वहां न्यायिक परिवर्तन की अनुमति है। उद्धृत करने के लिएः

" 26..... जहाँ अपराधी सामाजिक-आर्थिक मानसिक या दंडात्मक मजबूरियों से पीड़ित है, जो कानूनी अपवाद को आकर्षित करने या अपराध को कम करने के लिए अपर्याप्त हैं, वहां न्यायिक परिवर्तन की अनुमति है। अन्य सामान्य सामाजिक दबाव, जिनके प्रभाव को कम करने के लिए न्यायिक नोटिस की आवश्यकता होती है, विशेष मामलों में कम जुर्माना लगा सकते है। न्यायिक प्रक्रिया में असाधारण विशेषताएं, जैसे कि मृत्युदंड की सजा अपराधी के सिर पर लम्बे समय तक लटकी रहती है। अदालत को दयालू होने के लिए प्रेरित कर सकती है इसी तरह,

---

---

30. कुमुदीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1999) 4 एस. सी. सी. 108: (1999) एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 491.

31. अख्तर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1999) 6 एस. सी. सी. 60 1999 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1058

32. अमृत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2006) 12 एससीसी 79:(2007)2 एससीसी (सीआरआई) 397.

33. बिष्णु प्रसाद सिन्हा बनाम असम राज्य, (2007) 11 एससीसी 467 (2008)1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 766.

34. हरेश मोहनदास राजपूत बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 12 एससीसी 56:(2012) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 359

316 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2013] 9 एस. सी. आर.

यदि अपराध में शामिल और इसी तरह के अन्य लोगों को आजीवन कारावास का लाभ मिला है या यदि अपराध केवल रचनात्मक है, तो धारा 302 सपठित धारा 149, या फिर अभियुक्त ने किसी अन्य के उकसावे के तहत, बिना पूर्व चिंतन के अचानक कृत्य किया है, शायद न्यायालय मानवीय रूप से जीवन का विकल्प चुन सकती है, भले ही पत्नी की बेवफाई के उचित कारण या वास्तविक संदेह ने अपराधी को अपराध में धकेल दिया।..... "

(जोर दिया गया)

22. एडिगा अनाम्मा के मामले (ऊपर) को दलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1384 में तीन-न्यायाधीशों की

पीठ द्वारा बाद के निर्णय में मंजूरी की मोहर दी गयी थी। जिसमें यह भी कहा गया है कि "बचपन या उसके बाद की अवांछित प्रतिकूलताएँ भी एक कम करने वाला कारक होंगी।

23. एडिगा अनाम्मा के मामले (ऊपर) में इस अदालत ने कुछ अन्य बढाने वाले कारकों का भी उल्लेख किया गया है। उद्धृत करने के लिएः

> "26. ..... दूसरी ओर, इस्तेमाल किए गए हथियार और उनके इस्तेमाल का तरीका, अपराध की भयानक विशेषताएं और पीड़ित की असहाय, असहाय स्थिति और इसी तरह की अन्य बातें, एक कठोर सजा के लिए कानून का दिल चुरा लेती है। हम स्पष्ट रूप से ऐसी सभी स्थितियों को न्यायिक कंप्यूटर में दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि वे एक अपूर्ण और उतार चढाव वाले समाज में ज्योतिषीय रूप से असंभव हैं। जीवन या मृत्यु पर एक कानूनी नीति को तदर्थ मनोदशा या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है और इसलिए हमने प्रतिशोधात्मक क्रूरता को त्याग कर, निवारक पंथ में संशोधन करने और जीवन को खतम करने के चरम और अपरिवर्तनीय दंड के खिलाफ प्रवृत्ति पर जोर देने की कोशिश की है।"

(जोर दिया गया)

24. गरीबी जैसी सामाजिक-आर्थिक मजबूरियां भी ऐसे कारक हैं।

सुनील दामोदर गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य [कुरियन, जे.] 317

जिनपर न्यायालय को सजा सुनाते समय विचार करना चाहिए। यह दृष्टिकोण सुशील कुमार बनाम पंजाब राज्य (2009)10 एससीसी 434 के निर्णय में लिया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने अभियुक्त की अत्यधिक गरीबी के कारण मृत्युदंड देने से इन्कार किया। सुशील कुमार (ऊपर) के मामले में तथ्य वर्तमान मामले से बहुत मिलते-जुलते हैं। उस मामले में भी अभियुक्त ने अत्यधिक गरीबी के कारण अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों की हत्या कर दी थी। बाद में, उसने कथित तौर कुछ गोलियाँ खाकर अपनी जान लेने की कोशिश की। अभियुक्त को निचली अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी और उच्च न्यायालय द्वारा सजा की पुष्टि की थी। इस न्यायालय ने सजा को कम करते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया।

> " 46. अत्यधिक गरीबी ने अपीलार्थी को उसके परिवार के तीन बहुत करीबी और प्रिय सदस्यो- उनकी पत्नी, नाबालिग बेटा और बेटी की वीभत्स हत्या करने के लिए प्रेरित किया था। यह दिखाने के लिए रिकार्ड पर कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी आदतन अपराधी है। वह एक

शांतिप्रिय, कानून का पालन करने वाला नागरिक प्रतीत होता है। लेकिन चूंकि वह गरीबी से पीड़ित था, इसलिए उसने उसके परिवार को पूरी तरह से खत्म करने के बारे में सोचा ताकि सभी समस्याओं का अंत होगा। वस्तुतः हत्या का अपराध करने के बाद उसके द्वारा कुछ जहरीले पदार्थों का सेवन करने का यही कारण प्रतीत होता है।

47. किसी भी गवाह ने अतीत में अपीलार्थी के बुरे या असराहनीय व्यवहार के बारे में शिकायत नहीं की है। घटना के बाद कई लोगों का उनके घर जाना इस तथ्य का संकेत है कि उनके सभी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। वे अब लगभग पैतीस वर्ष के हो गए हैं। अवीलार्थी के सुधार और अच्छा नागरिक बनने की काफी अच्छी संभावनाएँ प्रतीत होती है।"

(जोर दिया गया)

25. हमारे समक्ष मामले में, यह साक्ष्य के रूप में सामने आया है कि अपीलार्थी आर्थिक और मानसिक मजबूरियों से पीड़ित था।

अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। न्यायालय के

पास उपलब्ध तथ्यों पर, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अभियुक्त से समाज के लिए खतरा या खतरा होने की संभावना नहीं है। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उनकी कोई पूर्व का आपराधिक पृष्ठभूमि रही हो। वास्तव में अपीलार्थी का इरादा अत्यंत गरीबी के कारण खुद सहित पूरे परिवार का खतम करने का था। मामले के इस पहलू की सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा व्याख्या नहीं की गई है, जिसमें माना था कि अपीलार्थी का इरादा केवल दूसरों को मिटा देने का था और उसने आत्महत्या के लिए प्रयास भी नहीं किया था, और वह आत्महत्या के लिए तैयार भी नहीं था। हमें डर है कि अदालतों ने साक्ष्य की उचित व्याख्या नहीं की है। यदि उसकी पुत्री ने उससे यह सवाल पूछते हुए नहीं रोका होता कि वह उसे क्यों मार रहा है, तो उसका इच्छित आचरण वैसा ही होता जैसा कि उसकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि उन सभी को दुनिया से जाने की जरूरत है। हृदय परिवर्तन का महत्वपूर्ण और निर्णयक मोड़ उसके साथ हुई बातचीत है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी और दो बेटों की हत्या को अंजाम दिया, उसने उन्हें चिल्लाने भी नहीं दिया, कोई सवाल पूछना तो दूर की बात है। यह संयोग से हुआ कि बेटी को चाकू से लगी चोटों के बावजूद, वह रोते हुए अपने पिता से सवाल करने में सफल रही कि वह इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहे थे। हृदय परिवर्तन इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि उन्होंने घायल बेटी को पानी पिलाया था। इसके बाद उन्होंने उसे खत्म

करने के लिए हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। उसने एक बार फिर उसे अपनी गोद में लेकर तकिये की मदद से उसका गला घोटने की कोशिश की। हालांकि, जैसा कि उसके अपने बयान से देखा जा सकता है, कि वह उसकी हत्या नहीं कर सका। इसके बाद, वह सीधे पुलिस स्टेशन गया और उसने जो कृत्य किया, उसका बयान दिया।

26. यदि हम अपराध करने के समय अपीलार्थी की परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में और अपराध परीक्षण और आपराधिक परीक्षण लागू करने पर मामले के तथ्यों का विश्लेषण करते हैं तो, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी के मामलों में नहीं आता है ताकि मौत की सजा दी जा सके। 'व्यक्तिगत रूप से अनिर्णायक और संचयी रूप से सीमांत तथ्य और परिस्थितियाँ आजीवन कारावास की कम सजा देने की और प्रवृत्त होती है।

सुनील दामोदर गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र [कुरियन, जे.] 319

27. उपरोक्त तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में, जबकि आई.पी.सी. की धारा 302 और धारा 307 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, हम सजा को निम्नानुसार संशोधित करते हैंः

(अ) आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए, अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।

(ब) आई.पी.सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए, अपीलार्थी को सात साल की अवधि के लिए कारावास सजा दी जाती है।

28. गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 600 मामले में (ऊपर) संविधान पीठ द्वारा दिये गए फैसले के अनुसार किसी दोषी को उम्रकैद उसके जैविक जीवन के अंत तक दिया जा सकता है। इसलिए यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि सजाएं लगातार चलेंगी। हालांकि हम स्पष्ट करते हैं कि यदि आजीवन कारावास की सजा कम की जाती है या किसी निर्दिष्ट अवधि (किसी भी मामले में, सीआर.पी.सी. की धारा 433ए को देखते हुए चौदह साल से कम नहीं होगी) में परिवर्तित की जाती है तो आई.पी.सी. की धारा 307 के तहत कारावास की सजा इसके बाद शुरू होगी।

29. अपीलें उक्तानुसार स्वीकार की जाती है।

अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अजन्ता अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।